

अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

केसर बनाम काशीराम आदि

किस्म मुकदमा:-212 आरटीए 1955

प्रकरण संख्या:-116/2024 G/CMS No. 2024/274

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

30.04.2025

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 3 टीटीडी ए खाता नं० 24 प०न० 150/23 (47) कि०न० 7 ता 9/0.759 है०, 11 ता 14/1.012 है०, 17 ता 20/1.012 है०, 21/2/0.228 है०, 22/2/0.228 है०, 23/2/0.228 है०, 24/2/0.228 है० कुल 3.695 है० अ०क० खातेदारी भूमि हैं। जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 की सत्यप्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। जैरवाद रकबा में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है० अ०क० खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं० 1 के नाम 253/739 हिस्सा यानि 1.265 है० अ०क० खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं० 2 के नाम 106/3695 हिस्सा यानि 0.106 है० अ०क० खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं० 3 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है० अ०क० खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं० 4 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है० अ०क० खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं० 5 के नाम 107/3695 हिस्सा यानि 0.106 है० अ०क० खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अवलोकन से साबित हैं। जैरवाद रकबा पूर्व में प्रार्थी के पति व अप्रार्थी नं० 2 ता 5 के पिता स्व० श्री सोहनलाल के नाम से था। स्व० श्री सोहनलाल का देहान्त निर्वसीयत अवस्था में होने के कारण जैरवाद रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 2 ता 5 के नाम ब०हि०ब० बतौर जायज वारिस विरासतन दर्ज हुआ। अप्रार्थी नं० 2 व 5 द्वारा स्वयं को प्राप्त विरासतन रकबा में से ब०हि०ब० 1.265 है० रकबा वर्ष 2022 में अप्रार्थी नं० 1 को बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरण सं० 622 अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज हो चुका है। जो कि संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से साबित हैं। जैरवाद रकबा अच्छी व खराब तथा समतल व उबड़ खाबड़ एवं उपजाउ व अनउपजाउ दोनो किस्म का है तथा जैरवाद रकबा जिप्सम भंडारण क्षेत्र में स्थित हैं। जिस कारण से जैरवाद रकबा में जिप्सम की काफी मात्रा हैं। जिस कारण से काफी किमती भूमि हैं। जैरवाद रकबा छोटे टूकड़े में स्थित हैं एवं मौके पर अविभाजित हैं। जिस कारण से प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 ता 5 छोटे-छोटे टूकड़ों के काश्तकार हैं। इसलिये अप्रार्थी नं० 1 ता 5 छोटे-छोटे टूकड़ों को न रखकर खाता विभाजन से पूर्व जैरवाद रकबा में अपने-2 हिस्सा को अजनबी केता को बैचान करने पर उत्तारु हैं। प्रार्थी एक खेती करने वाली महिला हैं। जो कि अपने पति के देहान्त पश्चात् मिली भूमि पर काश्त कर अपना गुजारा बसर कर रही हैं। जबकि अप्रार्थी नं० 1 राजनैतिक साठगांठ वाला व्यक्ति हैं। अप्रार्थी नं० 2 ता 5 उसके दबाब में हैं। यदि अप्रार्थी नं० 1 अपनी धमकी अनुसार कुयोजना में कामयाब होकर खाता विभाजन से पूर्व जैरवाद रकबा में अवैध जिप्सम खाता विभाजन से पूर्व निकाल लेता है या किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बैचान कर अथवा ठेका पर देकर जिप्सम निकालता है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली कानूनी कार्यवाही में प्रार्थी पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा जैरवाद रकबा का खुर्द बुर्द होने की पूरी सम्भावना बनी रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति सम्पूर्ण नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अच्छी भूमि खाता विभाजन में प्राप्त करने से वंचित हो जायेगी। व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी। जबकि प्रार्थी एक खातेदार हैं इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के हक में साबित हैं। कानूनन प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ भूमि को खुर्दबुर्द से बचाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक पाने की हकदार हैं।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रकबा अभी संयुक्त खाता में हैं। वाद पत्र न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन हेतु विचाराधीन हैं। खाता विभाजन से पूर्व सम्पत्ति की सुरक्षा करना न्यायालय का दायित्व हैं। अतः अप्रार्थीगण के बाद सूचना अनुपस्थित होने एवं कोई विपरीत साक्ष्य पेश नही होने के कारण न्याय हित में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ता वाद फ़ैसला अप्रार्थीगण विवादित भूमि चक 3 टीटीडी ए खाता नं० 24 प०न० 150/23 (47) कि०न० 7 ता 9/0.759 है०, 11 ता 14/1.012 है०, 17 ता 20/1.012 है०, 21/2/0.228 है०, 22/2/0.228 है०, 23/2/0.228 है०, 24/2/0.228 है० कुल 3.695 है० अ०क० खातेदारी भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)